



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 82 ]  
No. 82]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 1999/चैत्र 16, 1921  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 1999/CHAITRA 16, 1921

## सार्वजनिक सूचना संख्या 5 (आरई-99)/1997—2002

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1999

फा. सं. 1/94/180/504/ए एम 99/पी सी-4.—का. आ. सं. 283(अ) दिनांक 31-3-1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में यथाअधिसूचित नियंत्रित और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं द्वारा इ पी सी जी और अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में नियंत्रित दायित्व अवधि की बढ़ोत्तरी के लिए निम्नलिखित दिशा निर्धारित करते हैं :

1. 1.4.92 को या उसके बाद जारी ग्रीष्म लाइसेंसों के संबंध में, जहाँ लाइसेंस धारक निर्धारित समय सीमा के प्रतीक्षा नियंत्रित दायित्व को पूरा नहीं कर सका है, वहाँ वह सार्वजनिक मूल्य की तारीख से डेंड वर्क के लिए नियंत्रित दायित्व की अवधि बढ़ाने द्वारा ग्रावेन कर सकता है। उसे बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की तारीख से आयात की तारीख तक उपयोग में न लाई गयी हृत प्राप्त सामग्री पर 24% साधारण ब्याज सीमित लाइसेंस के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी और यदि वह बढ़ाई गई अवधि में नियंत्रित दायित्व को पूरा नहीं कर पाता तो इसे जब्त कर लिया जाएगा। बैंक गारंटी 31-3-2002 तक वैध होगी।

2. यह मुख्यमान्यता के अनुसार जारी किए गए इ पी सी जी लाइसेंसों के संबंध में नियंत्रित दायित्व अवधि में बढ़ोत्तरी के लिए योग्य सम्भाल लाएगा बश्यत की लाइसेंस धारक जो पूर्व निर्धारित समयावधि में आयात दायित्व को पूरा नहीं कर सका है वह नियंत्रि

दायित्व पूरा न कर सकने के सम्बन्धात माझा में 34 प्रतिशत साधारण बाल संहित सीमांशुक के लिए बैंक गारंटी देने विरोधी नियत दायित्व अधिकार में बद्दोत्तरी के लिए जावेदन कर सकता है ।

३१३ सार्वजनिक सूचना संख्या १-मार्ट टी सीडीपी संख्या/1990-93, दिनांक ३० मार्च, 1990 के तहत अधिसूचित मायात और नियत नीति 1990-93 खण्ड-१ इसमध्ये-समय पर व्यासांशोधित पैराग्राफ 197 ।

३२४ सार्वजनिक सूचना संख्या १-मार्ट टी पीडीपी संख्या/1992-97 दिनांक ३१ मार्च 1997 के तहत अधिसूचित नियत और मायात नीति 1992-97 इसमध्ये-समय पर व्यासांशोधित पैराग्राफ 38 ।

३३५ अधिसूचना संख्या २२४ संख्या ३१ 1992-97 दिनांक ३० जून 1992 के तहत अधिसूचित नियत और मायात नीति 1992-97 इनमें मूल १९९७ समय-समय पर व्यासांशोधित पैराग्राफ 38 ।

३४६ नियत व मायात नीति इसांशोधित संस्करण 1993 पैराग्राफ 38 व 46 ए समय समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या इमार ई१ 1992-97 दिनांक ३१ मार्च, 1993 ।

३५७ नियत व मायात नीति 1997 इसांशोधित संस्करण मार्च, 1994 पैराग्राफ 38 व 46 ए समय समय पर व्या संशोधित अधिसूचना संख्या ३३४ इमार ई१ 1992-97 दिनांक ३१ मार्च, 1994 ।

३६८ अधि सूचना संख्या १ इमार ई१ 1992-97 दिनांक ३१ मार्च, 1995 के तहत अधिसूचित नियत मायात नीति 1992-97 इसमध्ये समय पर व्या संशोधित संशोधित संस्करण मार्च, 1995 पैराग्राफ 38 ।

बड़ी ही इस अधिकारी में नियत दायित्व पूरा ना करने की वशा में एवं उल्लंघित बैंक गारंटी जल्द कर ली जाएगी, बैंक गारंटी 31-3-2002 तक वैध होगी ।

3. अवधि बढ़ाने के लिए जावेदन इस सार्वजनिक सूचना से ६० दिन के भीतर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे । जिस लाइसेंसिंग प्राधिकारी मूल रूप से वह लाइसेंस वही नियत दायित्व अधिकारी में बद्दोत्तरी हेतु सक्षम होगा ।

4. तथापि, जिन लाइसेंसों के संबंध में बालसाजी/धोकाघड़ी की जानकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को गिली हो उनके नियत दायित्व की पूर्ति की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसके मुलाका, जिन लाइसेंसों के संबंध में न्याय निर्णय आदेश फैले से जारी रह दिए गए हों उनके नियत दायित्व की पूर्ति की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी ।

5. जिन मामलों में लाइसेंसधारक ने इस सार्वजनिक सूचना के प्रत्यागति दी गई सुविधा का लाभ नहीं उठाया हो उन मामलों में इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से ६० दिनों की अवधि के समाप्त होने पर न्याय निर्णय प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।

6. उन मामलों में जहाँ, नियंत्रित दायित्व की पूर्ति इस सार्वजनिक सूची के जारी होने की तरीके से पहले तोक्सन नियंत्रित दायित्व की नियोनिस ग्राही के बाद की गई हो उन नियंत्रितों के मामले में विनियमन के प्रयोगन के द्वारा नियंत्रित दायित्व की नियोनिस ग्राही के भीतर पूरा किया गया मास लिया जाए।  
इसे लोकार्थि में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## MINISTRY OF COMMERCE

### PUBLIC NOTICE NO. 5(RE-99) /1997—2002

New Delhi, the 6th April, 1999

**F. No. 01/94/180/504/AM 99/PC-IV.**—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the Gazette of India extraordinary, Part-II—Section 3—Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-1997, the Director General of Foreign Trade hereby lays down the following guidelines for extension in export obligation period in respect of EPCG and Advance Licences :

1. In respect of Advance Licences issued on or after 1.4.92, where the licence holder has failed to complete his export obligation within the stipulated time limit, he can apply for extension of export obligation period for 1½ years from the date of the Public Notice on submission of a Bank Guarantee, covering the Customs duty together with 24% simple interest on the unutilised exempt material from the date of import upto 31.3.2001, which shall be forfeited in the event of non fulfilment of export obligation in the extended period. Bank Guarantee should be valid upto 31.3.2002.

The above facility shall also be available to Value Based Advance Licence after converting the same into a Quantity Based Advance Licence.

2. In respect of EPCG licences issued in pursuance of the following notifications, the licence holder shall be deemed to be eligible for extension of export obligation period upto 31.03.2001 provided the licence holder who has failed to complete his export obligation within the earlier stipulated time limit, applies for extension of export obligation period on submission of a Bank Guarantee, covering the Customs duty in proportion to the unfulfilled export obligation together with 24% simple interest thereon from the date of import upto 30.9.2001.

- i) Import & Export Policy 1990-93, Vol. I (Paragraph 197 as amended from time to time) notified under Public Notice No. 1-ITC (PN) 1990-93 dated 30<sup>th</sup> March, 1990;
- ii) Export & Import Policy 1992-97 (Paragraph 38 as amended from time to time) notified under Public Notice No. 1-ITC (PN) 1992-97 dated 31<sup>st</sup> March, 1992;
- iii) Export & Import Policy 1992-97 (Reprint June, 1992 - Paragraph 38 as amended from time to time) notified under Notification No. 22 (N.3) 1992-97 dated 30<sup>th</sup> June, 1992;
- iv) Export & Import Policy 1992-97 (Revised edition March, 1993 – Paragraphs 38 and 46A as amended from time to time) notified under Notification No. 1(Re) 1992-97 dated 31<sup>st</sup> March, 1993;

- v) Export & Import Policy 1992-97 (Revised edition March'94 – Paragraphs 38 and 46A as amended from time to time) notified under Notification No.34(RE) 1992-97 Dated 31<sup>st</sup> March, 1994;
- vi) Export Import Policy 1992-97 (Revised edition March'95 – Paragraph 38 as amended from time to time) notified under Notification No.1(RE) 1992-97 Dated 31<sup>st</sup> March, 1995.

The aforementioned Bank Guarantee shall be forfeited in the event of non fulfilment of export obligation in the extended period. Bank Guarantee should be valid upto 31.3.2002.

3. The request for extension shall be filed with the concerned licensing authority within a period of 60 days from the date of the Public Notice. The licensing authority which originally issued the licence shall be competent to grant extension in export obligation period.

4. However, no extension in export obligation shall be allowed in respect of the licences where misrepresentation/fraud has come to the notice of the licensing authorities. Further, in respect of licences where adjudicating orders have already been passed, no extension in export obligation period shall be admissible.

5. In such cases where the licence holder has not availed the facility accorded under this Public Notice, adjudication proceeding shall be initiated on the expiry of 60 days from the date of this Public Notice.

6. In such cases where export obligation has been fulfilled prior to the date of this Public Notice but outside the prescribed export obligation period, such exports shall be deemed to have been made within the ~~prescribed~~ Export Obligation period for the purpose of regularisation of the case.

This issues in public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade